

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December, 2019

**No. 74/2019—Central Tax**

**G.S.R. 953(E).**—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 4/2018—Central Tax, dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018, namely:—

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for the months/quarters from July, 2017 to November, 2019 by the due date but furnishes the said details in **FORM GSTR-1** between the period from 19th December, 2019 to 10th January, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 19th day of December, 2019.

[F. No. 20/06/09/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 4/2018-Central Tax, dated 23rd January, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018 and was subsequently amended by notification No. 75/2018-Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1252(E), dated the 31st December, 2018.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

**सं. 75/2019—केन्द्रीय कर**

**सा.का.नि.954(अ).**—केन्द्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2019 है।  
(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 36 के उपनियम (4) में, 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी, “20 प्रतिशत” अंक और शब्द के स्थान पर “10 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों के नियम 86 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**“86क. इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में उपलब्ध रकम के उपयोग की शर्तें.-**

- (1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त की श्रेणी से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में उपलब्ध इनपुट कर के प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग किया गया है या वह अपात्र है, उस सीमा तक जिस तक वह -

क) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग,-